EDITORIAL

Message of Mysore NEC

The Extended National Executive Committee meeting of our union NFTE (BSNL) held at Mysuru (Karnataka) from 8th to 10th June, 2019. After our notification of the meeting a new Govt is formed with a full majority. The membership verification of recognition of representative unions for non-executive employees also notified. The atmosphere of the meeting was very pleasant on assuming as communication and I.T. Minister by Shri Ravi Shanker Prasad Ji. Earlier also he was given the responsibility in the year 2014, when he raised the issue of call dropping and took the Private Teleo's also on task.

The happiness among the members was for the statement regarding revival of BSNL/MTNL by the Hon'ble MOC after his assuming the post.

It is fact that in his first short tenure, the Company turn around towards vertical up gradation and achieved 3 years regular operational profit. Three days marathon discussions took place at Mysuru and all most all were concern with the financial viability of BSNL and the pending legitimate demands of the workers.

It came out from the several speakers that when the Govt was committed to keep the company viable, at the eve of corporatization, how the company is passing through a very grim and critical situation. Whether the administrative ministry being the owner with total equity did not monitored and took care the functioning of Company? Now it is told by the BSNL management as well by the Govt that the huge number of staff are problem of the Company as they are taking half or more revenue of Company as salary and other allowances. It is a very light thought without ins and out study of the situation.

Now the condition is at all alarming. The management is not able to pay the rent of the rented building, Electricity bills are not being paid causing closure of BTS's/Telephone Exchanges, vendors and Contractual laboures are deprived to get their salary and payment of their pending claims. Now the Company is in a debt of Rs. 19600 crore and other liabilities are crossing Rs. 10,000 crores. Even staff are getting only take home salaries. Their deductions are not paid to the concern institutions.

We absorbed that one hand the company is passing through hardship even minimum required maintenance funds are not being transferred to field units by Corporate office, several claims of T.A, Medical bills are lying pending and at other hand our rank and file are deprived for non implementation of third wage revision, Pension Revision. The 4G spectrum is not allotted to BSNL. Even the arbitrary deduction of pension contribution on maximum of the scale is not resolved by the DOT. The younger generations are not protected as per DPE guidelines even after clear assurance given by CMD. The superannuation benefit fund is not increased from 5% to 8%.

In this scenario the Mysuru meeting feels the situation of the Company is in very grim and critical. It was unanimous opinion of the members that only our united contribution for Company can help it to come over the crisis, simultaneously the Govt. the real owner of the entity should arrange one time measure financial support to bail out the company.

संपादकीय

मैसूर में संपन्न कार्यकारिणी का संदेश

दिनांक 8 से 10 जून 2019 तक मैसूर (कर्नाटक) में एन.एफ.टी.ई (बी.एस.एन.एल) की कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अधिसूचना जारी होने के बाद दो प्रमुख समाचार प्रकाश में आए प्रथम भारत में प्रचंड बहुमत के साथ एक नयी सरकार गठित हुई और दूसरा नॉन एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघ को निर्वाचित करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के संचार एवं प्राद्योगिकी मंत्री का पदभार ग्रहण करने के समाचार से सभा में एक सुखद वातावरण संचारित था। पूर्व में 2014 में भी इन्हें यह जिम्मेवारी दी गई थी जब उन्होंने "काल ड्रापिंग" के मामले में निजी दूरसंचार प्रचालकों की भी सुधी ली थी। श्री प्रसाद के पदभार ग्रहण के उपरांत अपने पहले संवाद में बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल की पुनरूद्धार की बातें कही है इसलिए भी सभा में उपस्थित समुदायों में खुशी तैर रही थी।

यह सत्य है कि श्री रविशंकर प्रसाद जी के प्रथम दौर में थोड़े समय के मंत्रित्वकाल में कंपनी सापेक्षतः अग्रसर होते हुए लगातार तीन वर्षा तक संचालन लाभ में रही।

मैसूर में तीन दिनों तक व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुई। चर्चा में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं की चिंता कंपनी की आर्थिक जीवंतता एवं कर्मचारियों की लंबित वाजिब मांगों के प्रति केंद्रित रही।

सभा में तथ्य भी सामने लाये गये कि सन् 2000 में डी.ओ.टी को जब नियमित किया जा रहा था तो कंपनी के आर्थिक रूप से प्रबल जीवंतता देने की आश्वासन तत्कालीन भारत सरकार ने दी थी, तो क्या कंपनी के वास्तविक स्वामित्वधारी दूरसंचार विभाग ने कंपनी के संचालन में उदासीनता वरीयता उसका सामायिक अवलोकन नहीं किया? आखिर कंपनी को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए जिम्मेवार कौन है?

अभी सरकार और बी.एस.एन.एल प्रबंधन की ओर से यह कहा जाने लगा है कि बी.एस.एन.एल में कर्मचारियों की भारी संख्या ही इस कंपनी की समस्या है क्योंकि पूर्ण राजस्व के आधे या उससे अधिक राशि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर खर्च हो जाते हैं। यह एक सतही सोच है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। ऐसा इसलिए है कि उच्चस्तरीय प्रबंधन एवं सरकार की ओर से स्वामित्व रक्षण करने वाले अधिकारियों ने कभी गंभीरता से कंपनी के संचालन पर सावधानी नहीं करती और जब मुसीबत सर चढ़ गई तो कर्मचारियों की अधिकता नजर आने लगी है।

अभी स्थिति चिंताजनक हो गई है। प्रबंधन, भाड़े के मकानों का किराया का भुगतान नहीं कर पा रही है। प्रतिष्ठानों के बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण सेवाएं बाधित हो रही है। ठेकेदारों, ठेका कर्मचारियों के देयको एवं मजदूरी का भुगतान संबित है।

अभी कंपनी 19600 करोड़ रूपये के कर्ज से दब चुकी है। कंपनी पर 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की देनदारी हो चुकी है। कर्मचारियों से की गई कटौती को संबंधित प्रतिष्ठानों को नहीं दी जा रही है।

हमने महसूस किया है कि कंपनी एक तरफ भारी आर्थिक दबाब में गुजर रही है जहां न्यूनतम अनुरक्षण कोष भी कॉर्पोरेट कार्यालय से कार्य क्षेत्र में स्थानातंरित नहीं हो रहे हैं। टी.ए. एवं मेडिकल के असंख्य देयक लंबित है और दूसरी और कर्मचारियों से संबंधित वाजिब समस्याएं भी कतार में हैं, मसलन तृतीय वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन, 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन, यहां तक की बी.एस.एन.एल कर्मचारियों के पेंशन अंशदान हेतु निरंकुश तरीके से उनके अधिकतम वेतनमान पर अंशदान की वसूली के मामले को भी डी.ओ. टी निष्पादन नहीं कर पाई है। कंपनी में नवनियुक्त युवा कर्मियों की भी सुरक्षा लचर है। डी.पी.ई के अनुदेशों के तहत प्रदत्त सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई गई है।

यहां तक कि सेवानिवृत्ति कोष की राशि पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का माननीय सी.एम.डी.,बी. एस.एन.एल के द्वारा स्पष्ट आश्वासन के बावजूद भी इसे अंजाम नहीं दिया गया। चारों तरफ निराशा बढ़ती जा रही है।

इस परिपेक्ष्य में मैसूर की बैठक में महसूस किया कि बी.एस.एन.एल की स्थिति अत्यंत गंभीर एवं नाजुक हो चुकी है। इस सभा कि सर्वसम्मत राय थी कि कंपनी का पुनरूद्धार कर्मचारियों की सपूर्ण एकता के साथ सहयोग से ही संभव है साथ ही भारत सरकार जिसका पूर्ण स्वामित्व के अधीन बी.एस.एन.एल संचालित है को एक बार आर्थिक सहयोग देकर कंपनी को कठिन दौर से बाहर करनी चाहिए।